<u>देश के नाम प्रधान मंत्री का संदेश</u>

4 जून, 2008

प्यारे देशवासियों,

आज मैं एक ख़ास बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। आपसे बात किए हुए कुछ समय गुजर चुका है। पिछले कुछ सालों में हमारा देश दुनिया की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। इस तरक्की की वज़ह से, सरकारी आमदनी में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इसे हमने अपने देश के लोगों की भलाई के कामों में लगाया है -- चाहे किसानों की भलाई के लिए हो, चाहे बेरोज़गार को रोज़गार दिलाने के लिए हो या देश में Infrastructure को मज़बूत बनाने के लिए हो।

मुझे आपसे बात करते हुए इस बात का भरोसा है कि सभी भारतवासी अपनी मेहनत और लगन से देश की तरक्की की रफ्तार को तेज बनाए रखेंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि हमारी सरकार ऐसी नीतियों पर चलती रहेगी, जिससे समाज के सभी तबकों को तरक्की का लाभ मिले, जिससे सभी लोग विकास के हिस्सेदार बनें और किसानों, कारीगरों और मजदूरों को फायदा हो।

पिछले चार सालों में, हमने ज्यादातर ऐसे कार्यक्रम शुरु किए हैं जिनका लाभ सीधे गरीबों और समाज के कमजोर तबकों को मिलता है। आज देश के हर ग्रामीण इलाके में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है जिससे सभी गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। किसानों और खेती को ख़ास तवज्जो दी जा रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि 10 साल पहले की तुलना में आज कृषि की पैदावार ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में खूब विकास हुआ है। Primary, Secondary और उच्च शिक्षा में हज़ारों नई संस्थाएं शुरू की गई हैं। बच्चों को दोपहर का खाना सभी स्कूलों में देकर हम बच्चों का कुपोषण दूर करने में लगे हुए हैं। भारत निर्माण और जवाहर लाल नेहरू Urban Renewal मिशन के माध्यम से हम ग्रामीण और शहरी इलाकों में बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। मुझे इस बात की तसल्ली है कि हमारी इन कोशिशों के नतीज़े देखने को मिल रहे हैं और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि गरीबी, अशिक्षा और बीमारी हटाने के लिए हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

प्यारे देशवासियों,

आप लोगों की तरह मुझे भी इस बात की चिंता है कि हाल के कुछ महीनों में, हमारी इस बढ़ती तरक्की के साथ-साथ मंहगाई भी बढ़ रही है। हमारी सरकार ने बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारा मक़सद यह है कि समाज के गरीब तबकों को मंहगाई की मार से बचाया जाए।

आप सभी जानते हैं कि बढ़ती मंहगाई के दो अंतरराष्ट्रीय कारण हैं। पहला, दुनिया भर में बढ़ती हुई अनाज की कीमतें। और दूसरा, दुनिया भर में Petrol की बढ़ती हुई कीमतें।

अनाज की पैदावार और खरीद को बढ़ाने के लिए, अनाज के Export को रोकने के लिए और अनाज को राशन की दुकानों के माध्यम से आप तक पहुँचाने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। शुरुआती ख़बरों से ऐसा लगता है कि इस साल बारिश अच्छी होने की उम्मीद है। हमारे इन कदमों से और एक अच्छी बारिश की उम्मीद से अनाज की कीमतें अब बढ़ नहीं रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले महीनों में अनाज के दाम बढ़ने से रूक जाएंगे।

जहां तक अनाज का सवाल है, हमारा देश उतना अनाज पैदा कर लेता है जितनी हमें जरूरत है। हमें दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इसके लिए हम अपने किसानों को सलाम करते हैं। हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए और उन्हें ज्यादा खुशहाल बनाने के लिए काम करना जारी रखेगी। किसानों को उनके उत्पादन के लिए उचित मूल्य देने होंगे। इससे अनाज की कीमतों में थोड़ी बढ़ोत्तरी जरूर होगी लेकिन यही एक रास्ता है जिससे हम अनाज के उत्पादन को बढ़ा सकेंगे और अनाज की किल्लत को दूर कर पाएंगे।

लेकिन तेल के मामले में क़ुदरत ने हमारा साथ नहीं दिया है। हमें तेल की कमी को पूरा करने के लिए इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लाना पड़ता है। इसकी वजह से दुनिया में बढ़ती तेल की कीमतों का असर हम पर भी पड़ता है। इससे हम बच नहीं सकते। क्योंकि हमारा खुद का तेल उत्पादन काफी कम है। यदि हम तेल की कीमतों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि 2004 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस वक्त एक बैरल कच्चे तेल की कीमत 40 अमेरिकी डालर से कम थी। आज उसी एक बैरल कच्चे तेल की कीमत 130 अमेरिकी डालर के बराबर हो गई है। यह तीन गुणा से भी ज्यादा की बढ़ोत्तरी है।

दुनिया भर में बढ़ती तेल की कीमतों की वजह से हमारी तेल कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकारी खजाने पर भी काफी बोझ पड़ रहा है। पिछले एक साल में ही तेल की कीमतें दो गुणा बढ़ गयी हैं। फिर भी हमारी सरकार ने पेट्रोल और बाकी किस्म के तेल के दामों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की। हमने चार सालों में केरोसीन के दामों को छुआ तक नहीं है।

प्यारे देशवासियों,

हमारी सरकार की हमेशा यही कोशिश रही है कि बढ़ रही तेल की कीमतों का असर आपके ऊपर कम से कम पड़े। हमारी मंशा यह है कि अधिक से अधिक लोगों को बढ़ती कीमतों से महफूज रखें। लेकिन देश के सरकारी खजाने पर और अर्थ-व्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ा है। हम हमेशा ऐसे नहीं कर सकते। हमें इस बदलती हुई तस्वीर के अनुसार अपने आपको बदलना

होगा। हमें तेल के इस्तेमाल में किफायती बनना होगा। और तेल को खरीदने के लिए उसके सही दाम भी चुकाने होंगे।

बढ़ रही तेल की कीमतों के असर से हम यहां के तेल की कीमतों को हमेशा बचा कर नहीं रख सकते। हमारी तेल कंपनियां दिन-ब-दिन घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकतीं। यदि ऐसा ही रहा तो वे बाहर से तेल खरीदने के काबिल नहीं रहेंगी।

तेल कंपनियों को कुछ हद तक राहत देने के लिए केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और बाकी तेलों पर taxes को काफी हद तक घटाया है, लेकिन केन्द्र सरकार के सामने विकास से संबंधित खर्चे और बाकी खर्चों की जरूरतों के मद्देनजर हम पेट्रोल और बाकी किस्म के तेलों पर टैक्स को पूरी तरह से नहीं हटा सकते। इसीलिए, हमें तेल की कीमतों को थोड़ा-बहुत बढ़ाना ही होगा।

हालांकि, हमारी कोशिश रही है कि हम तेल की कीमतों को कम से कम बढ़ाएं। हम पेट्रोल को 5 रूपए प्रति लीटर, डीजल को 3 रूपए प्रति लीटर और LPG के हर एक सिलेण्डर पर 50 रूपए बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। मिट्‌टी का तेल गरीबों के लिए एक अहम ईंधन है और इसलिए हमने इसके दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाए हैं। हम अभी भी हर एक LPG सिलेण्डर पर 250 रूपए और केरोसीन पर 20 रूपए प्रति लीटर का बोझ अपने कंधों पर ले रहे हैं। हमने जो बढ़ोत्तरी की है, वह जितनी भी कम हो सकती थी, उतनी ही है। अभी भी अधिकांश बोझ सरकार और तेल कंपनियों पर ही है।

केन्द्र सरकार, तेल कंपनियां और आप सब मिलकर इस बड़े बोझ को अपने कंधों पर ले रहे है। अब यह जरूरी है कि देश की सभी राज्य सरकारें, जिनमें से कई सरकारें पेट्रोल और बाकी तेलों पर काफी शुल्क लगाती हैं, वे भी आगे आकर शुल्कों और taxes को घटायें और अपना योगदान दें।

मेरे देशवासियों,

इन फैसलों से, दो लाख करोड़ रुपए से अधिक के घाटे का केवल एक दसवां हिस्सा ही पूरा हो पाएगा। अभी भी लगभग 90 फीसदी घाटे को पूरा किया जाना है। यह बचा हुआ घाटा जो तकरीबन एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए का है, उसका पूरा बोझ सरकार उठाने जा रही है। Excise और Custom शुल्कों में कमी लाकर हम बाईस हजार करोड़ रुपए का बोझ उठाने जा रहे हैं। बाकी एक लाख पचास हजार करोड़ रुपए के घाटे को तेल कंपनियाँ अपनी आय से और सरकार द्वारा दिए जाने वाले Oil Bond से पूरा करेंगी।

मेरे देशवासियों,

तेल की कीमतों में हमने मामूली बढ़ोत्तरी की है। फिर भी इससे काफी लोग खफा होंगे। लेकिन आपको याद रखना होगा कि सरकार करोड़ों रुपए का कर्जा oil bonds के रूप में उठा रही है। हमारी तेल कंपनियां भी काफी नुकसान उठा रही हैं।

लेकिन, मैं देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि बांड जारी करना, कर्जा उठाना और घाटे को तेल कंपनियों पर डाल देना इस समस्या का कोई पक्का समाधान नहीं है। हम सिर्फ अपना बोझ, अपने बच्चों पर डाल रहे हैं। उन्हें इस कर्ज को वापस चुकाना होगा। अपनी तेल कंपनियों को घाटे में डाल कर हम उन्हें कमजोर बना रहे हैं। बढ़ती अर्थव्यवस्था को तेल की जरूरत है और तेल कंपनियों को कमजोर बनाकर हम अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए, हमें कई मोर्चों पर नए उपाय करने की जरूरत है। आने वाले समय में हमारे देश के पास ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक ठोस रणनीति होनी चाहिए।

हम सब ऊर्जा की बचत करके देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। सभी देशवासियों से मेरी गुज़ारिश है कि वे हर कदम पर और हर समय ऊर्जा की बचत करें। चाहे वह पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, LPG हो, बिजली हो या पानी हो। हमें सभी का सही तरीके से इस्तेमाल करने की आदत डालनी चाहिए। हमें सौर, हवा, परमाणु और अन्य नई किस्म के ऊर्जा के साधनों की खोज में लगना होगा। चाहे ये साधन जहां कहीं भी हों।

मेरे प्यारे देशवासियों,

आज हमारे मुल्क के अधिक से अधिक लोग आर्थिक तरक्की का लाभ उठा रहे हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तमाम लोगों के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महफूज मुस्तकबिल की जमानत दे। हमें सिर्फ अपने लिए और आज के लिए नहीं सोचना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि आइंदा नस्लों के लिए क्या चीज अच्छी होगी। हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए क्या चीज बेहतर होगी। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाएं जिसमें उन्हें अनाज की या ऊर्जा की कमी न हो।

आज जो कदम हमने उठाए हैं, वो इसी सोच के अनुसार हैं। मुझे उम्मीद है कि एक मजबूत, महफूज और सुरक्षित भारत बनाने में आप सब मिलकर काम करेंगे। एक ऐसा भारत जहां आम आदमी अपने आपको सुरक्षित, सलामत और खुश महसूस करे और एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद रखे। हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और यदि हम साथ मिलकर काम करेंगे तो यकीनन हम उस सुनहरे भविष्य को हासिल कर सकेंगे।

जय हिन्द!